भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2716**
16.03.2026 को उत्तर देने के लिए

सांख्यिकीय आंकड़ा प्रणालियों में सुधार के लिए उठाए गए कदम

2716. डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश की सांख्यिकीय आंकड़ा प्रणालियों में अधिक दक्षता, विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त सुझावों/अभ्यावेदनों की जांच की है तथा उन पर कार्रवाई की है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में इष्टतम अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियों और प्रासंगिक विदेशी कानूनों का अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो सांख्यिकीय आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए कौन से प्रमुख उपाय चिह्नित किए गए हैं;

(ग) विश्वसनीय सांख्यिकीय आंकड़ा एकत्रित करने और गलत आंकड़ों की शुद्धि और अद्यतन करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आंकड़ा संग्रहण और प्रसार की प्रक्रियाओं में जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए लिए शुरू किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) मंत्रालयों/विभागों, शिक्षाविदों, डेटा उपयोगकर्ताओं आदि सहित हितधारकों से प्राप्त सुझावों/प्रतिक्रियाओं की नियमित रूप से जांच करता है और सांख्यिकीय डेटा प्रणालियों की दक्षता, विश्वसनीयता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, जहां भी उचित पाया जाता है, उन्हें शामिल करता है।

(ख) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), सांख्यिकी आंकड़ों की सटीकता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए उपाय करते हुए भारतीय संदर्भ में इसकी उपयुक्तता और भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली में संभव अभिग्रहण/संयोजन के लिए वैश्विक सांख्यिकी मानकों और सर्वोत्तम पद्धतियों की जाँच करता है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में आधिकारिक सांख्यिकी के

उत्पादन और प्रसार में अच्छी पद्धतियों और पेशेवर नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए मई 2016 में संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक सांख्यिकी के मूलभूत सिद्धांतों (यूएनएफपीओएस) को अपनाना शामिल है। अन्य पहलों में दिनांक 12.02.2026 को जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की नई श्रृंखला जिसमें 2024 को नया आधार बनाया गया है (पहले का आधार 2012 था) में प्रयोजन के अनुसार व्यक्तिगत उपभोग वर्गीकरण (सीओआईसीओपी) - 2018 रूपरेखा को अपनाना शामिल है, , और नवंबर 2025 में सभी आर्थिक कार्यकलापों के अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण (आईएसआईसी) संशोधन 5 के अनुरूप राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2025 जारी करना शामिल है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप, एमओएसपीआई ने व्यापक डेटा सामंजस्य/मानकीकरण पहल भी शुरू की है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सांख्यिकीय गुणवत्ता मूल्यांकन रूपरेखा (एसक्यूएएफ) की शुरूआत और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण मानकों के साथ अनुरूपता शामिल है। एसक्यूएएफ, जो यूएन राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन रूपरेखा (यूएन एनक्यूएएफ) 2019 पर आधारित है, अधिक दक्षता, विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की अंतर्निहित अवधारणाएं और कार्यप्रणाली संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, 2008 के अनुरूप हैं। इसके अलावा, सीपीआई और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष डेटा प्रसार मानकों (एसडीडीएस) का पालन करते हैं।

(ग) विश्वसनीय सांख्यिकीय डेटा संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के डेटा संग्रहण के लिए अंतर्निर्मित सत्यापन जांच, एआई-सक्षम चैटबॉट और बहुभाषी इंटरफेस आदि को शामिल करते हुए ई-सिग्मा प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करना शामिल है। ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उपयोग से डेटा संग्रहण के चरण में एकरूपता सुनिश्चित होती है और सर्वेक्षण डेटा को वास्तविक समय में प्रस्तुत करने और सत्यापित करने में सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त, एकत्रित डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वास्तविक जांच और निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता है, साथ ही फील्ड स्टाफ को नियमित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एमओएसपीआई अपनी सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण सहायता (एसएसएस) उप-योजना के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमता निर्माण को बढ़ाने में भी सहायता करता है, जिसका उद्देश्य उप-राज्य स्तर पर विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़ों को एकत्र करने, संकलित करने और प्रसारित करने के लिए राज्य सांख्यिकी प्रणाली की सांख्यिकी क्षमता और संचालन में सुधार/सुदृढ़ करना है।

(घ) एमओएसपीआई ने डेटा संग्रहण और प्रसार में जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं, जिनमें मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने सांख्यिकीय उत्पादों का अग्रिम रिलीज कैलेंडर (एआरसी) रखना शामिल है। एमओएसपीआई की नई वेबसाइट, जीओआईस्टैट्स के मोबाइल एप्लिकेशन, ई-सांख्यिकी पोर्टल, माइक्रोडाटा पोर्टल और डेटा आदान-प्रदान के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इन्टरफेस (एपीआई) के उपयोग से डेटा का प्रसार और सुलभता काफी हद तक बढ़ाई गई है। एमओएसपीआई ने डेटा स्रोतों, संग्रह विधियों पर स्पष्टता प्रदान करने और डेटासेट की खोज क्षमता को बढ़ाने के लिए मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच एक राष्ट्रीय मेटाडेटा संरचना (एनएसडीएस) भी प्रसारित की है। सांख्यिकीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डेटा उपयोगकर्ताओं/हितधारकों के साथ नियमित रूप से संवाद भी आयोजित किए जाते हैं।

*****